

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सीएम नायब सैनी ने की घोषणा

कुरुक्षेत्र का थीम पार्क अब होगा 'केशव पार्क'

विनोद जिंदल/हस्त कुरुक्षेत्र, 11 दिसंबर

धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 18 हजार स्कुली बच्चों ने गीता के 18 श्लोकों का पाठ कर इतिहास रच दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि कुरुक्षेत्र का थीम पार्क अब 'केशव पार्क' के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ इसे विश्वभर में पहचान दिलाने का प्रयास है।



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रुद्राक्ष का पीठा भेंट करते हुए।

कुरुक्षेत्र में बनेगा बाईपास: नायब सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए संवैधानिक मंजूरी दी है और इसका काम जल्द शुरू होगा। इससे कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर अब 48 कोस यात्रा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र को मसुरा और हरिद्वार से जोड़ने के लिए रेल सेवा शुरू होगी। श्री कृष्णा साहित्य योजना के तहत महाभारत से संबंधित 134 स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

गीता का ज्ञान युवाओं के लिए महत्वपूर्ण: शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कहा कि 5161 साल पहले भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें निरवधार्य भाव से कर्म करने का संदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है, वह हमेशा सफलता की उचाइयों को प्राप्त करता है। गीता के उपदेशों को आज की युवा पीढ़ी को समझकर अपने जीवन में आरना चाहिए।

करने की प्रेरणा देती है। यह संदेश आज के प्रबंधकों और नेताओं के लिए भी प्रेरणादायक है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गीता जयंती पर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। गीता न केवल भारत की बल्कि पूरी मानव जाति की धरोहर है। तंजानिया की पर्यटन मंत्री पिंडी चाना ने कहा कि कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थल की अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता है। यह वह

दिनेश भारद्वाज/ट्रिब्यून चंडीगढ़, 11 दिसंबर

हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की तैयारी तेज हो गई है। आठ नगर निगम, चार नगर परिषद और 22 नगर पालिकाओं के चुनाव जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में कराए जाने की संभावना है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने की योजना बनाई है। इसके बाद चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।



मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) भी सक्रिय हो गया है, और विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है। मतदाताओं को लुभाया जा सके। पार्टी का जोर उन पाठकों को दर्शक बनाने पर है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर कांग्रेस का साथ दिया था। ऐसे पाठकों की सूची तैयार की जा रही है, और भाजपा इस बार नए चेहरों पर दांव लगाने की योजना बना रही है। कांग्रेस पारंपरिक तौर पर नगर निगम के चुनाव पार्टी सिम्बल पर लड़ती है, लेकिन नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन करती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को पुनर्गठित कर सकती है ताकि भाजपा के शहरी प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके।

प्रदेश में निकाय चुनावों की तैयारी का बजा बिगुल

8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 पालिकाओं में होगी जंग मेयर तथा परिषद व पालिका में चेयरमैन के होंगे डायरेक्ट चुनाव। प्रदेश सरकार भी तैयारी में जुटी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी संगठन ने मेयर और चेयरमैन पद के लिए अनुभवी और नए चेहरों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है।

विधानसभा चुनाव की तर्ज पर भाजपा उतार सकती है उम्मीदार

भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में मिली जीत का फायदा निकाय चुनावों में भी मिलेगा। भाजपा निकाय चुनावों को विधानसभा चुनावों की तर्ज पर लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी ने पहले भी कई वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया था और यह फार्मूला सफल रहा। अब इसे निकाय चुनावों में लागू किया जा सकता है। भाजपा मेयर और चेयरमैन पद के लिए ऐसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार सकती है जो विधानसभा टिकट से वंचित रह गए थे। मेयर पद की बढ़ी अहमियत के कारण कई नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में मेयर का दर्जा विधायक और सांसद से भी ऊपर होता है, जिससे यह पद और आकर्षक बन गया है।

भाजपा नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है।



भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में मिली जीत का फायदा निकाय चुनावों में भी मिलेगा। भाजपा निकाय चुनावों को विधानसभा चुनावों की तर्ज पर लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी ने पहले भी कई वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया था और यह फार्मूला सफल रहा। अब इसे निकाय चुनावों में लागू किया जा सकता है। भाजपा मेयर और चेयरमैन पद के लिए ऐसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार सकती है जो विधानसभा टिकट से वंचित रह गए थे। मेयर पद की बढ़ी अहमियत के कारण कई नेता इस पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में मेयर का दर्जा विधायक और सांसद से भी ऊपर होता है, जिससे यह पद और आकर्षक बन गया है।

एटी-इन्फ्रामेसी को अवसर में बदलना चाहती है सरकार

तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद, सरकार एटी-इन्फ्रामेसी की छाया से बाहर निकलने के लिए निकाय चुनावों को सकारात्मक माहौल में करवाना चाहती है। भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा चुनावों में मिली जीत का फायदा निकाय चुनावों में भी मिलेगा।

चुनाव आयोग की तैयारी

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। आयोग ने 6 जनवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने जिला उपायुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को चुनावी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं।

17 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

23 दिसंबर तक दावे, आपत्तियां और संशोधन किए जा सकेंगे।

27 दिसंबर तक दावों का निपटारा किया जाएगा, और अंतिम सूची 6 जनवरी को जारी होगी। इसके बाद चुनावों की घोषणा की जाएगी।

यहां होंगे चुनाव

निगम: गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत और यमुनानगर। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम में से 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे हैं।

नगर परिषद: अम्बाला कैट, पटौटी मंडी, थानेसर और सिरसा।

नगर पालिकाएं: बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहार, सिवाली, फरुखनगर, जाखल मंडी, नारनौद, बेरी, जुनावा, कलायत, पंडरी, इंद्रा, नीलोखेड़ी, अरेली मंडी, कनीना, तावड़, हथौन, कलाना, कलालवाली, खरखोटा और रादौर। मानेसर नगर निगम में अभी तक एक बार भी चुनाव नहीं हुए हैं।

गुरुग्राम व फरीदाबाद में 60 दिन में मिलेगा सीएलयू, 90 दिन में मंजूर होगा बिल्डिंग प्लान

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और एफएमडीए) की 16-16 सेवाओं को अधिसूचित किया है। इस संदर्भ में हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार, दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) की अनुमति 60 दिनों के भीतर दी जाएगी, जबकि बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति 90 दिनों में प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिना किसी अपवाद के मामलों में 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किए जाएंगे।



पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत ईंट-भट्टी और चारकोल भट्टी के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेंज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे। जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे, जबकि पानी का रिसाव और पाइप टूटियों का सुधार 10 दिनों में ओवरफ्लो की समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनेहोल पर ब्लॉकज या ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा।

दोनों प्राधिकरणों की पंपिंग मशीनों, इलेक्ट्रिक, वायरिंग और वितरण प्रणाली में नए टाइल बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि डीएचबीवीएनएल की याचिका जनहित में नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेरपाल की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।

हाईकोर्ट ने गोला-बारूद डिपो में नये बिजली कनेक्शन देने से किया इन्कार

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गोला-बारूद डिपो के 300 से 900 मीटर के अधिसूचित क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन जारी करने, लोड बढ़ाने और टाइल बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि डीएचबीवीएनएल की याचिका जनहित में नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेरपाल की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।

डीएचबीवीएनएल ने अपनी याचिका में 18 दिसंबर, 2018 के आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया था, ताकि डिपो के 300 से 900 मीटर के क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने की अनुमति मिल सके। अदालत ने कहा कि 18 दिसंबर 2018 के आदेश में डीएचबीवीएनएल को केवल गोला-बारूद डिपो के बाहरी क्षेत्र में स्थित घरों को अस्थायी कनेक्शन देने की अनुमति दी गई थी, न कि वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों का। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह मामला गुरुग्राम के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेरपाल की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।



अब मामले की सुनवाई 13 फरवरी 2025 को होगी

चालती चाकरी

सत्यवीर नाइडिया

काया रहे निरोग जै, सुख पहला यो खास। माया हो घर म्हें दिखे, दुज्जा सुख अहसास। दुज्जा सुख अहसास, फेर सुख की सुणा बारी। घरों सुलकछण नार, पूत हो आयाकारी। आगे कोन्ही ओड़, तोड़ यो जग म्हें छाया। सारे सुख बेकार, निरोगी जै ना काया।।

पंकज अग्रवाल को अतिरिक्त प्रभार

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पंकज अग्रवाल को हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

SBI स्टेट बैंक आफ इंडिया

स्ट्रेट्स एसेट्स रिक्वैरी ब्रांच, 40 एसडीए कमर्शियल कम्प्लेक्स, जोनल कार्यालय इमारत, कसुमपट्टी, शिमला-171009 फोन नं. 0177-2626796, ई-मेल: sbi.18185@sbi.co.in

डिमांड नोटिस

सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत सूचना

Table with 5 columns: क्रम नं., कांस्टीटोर का नाम, जल की जाने वाली स्थलित परिसर/सिंचन/विद्युत/पला, सूचना की तिथि, एप्लीकेशन की तिथि, बकाया राशि (नोटिस की तिथि के अनुसार)

नोटिस की वैधता के लिए आवश्यक है कि सूचना को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, अन्यथा सिविल प्रोसेचर कोड के अंतर्गत सरफेसी एक्ट के अंतर्गत सूचना को जारी किया जाएगा।

कानून का ध्यान रखते हुए सूचना को जारी करने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (8) की व्यवस्थाओं की ओर धियाना जाता है।

दिनांक: 11.12.2024 स्थान: शिमला (हि.प्र.) अधिकृत अधिकारी।

Advertisement for pnb Housing Finance Limited, including contact information and details about housing loans.

फतेहाबाद में नहीं गुंजेगी रेल की सीटी

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

फतेहाबाद जिले में रेल की सीटी घोषणाओं में ही सुनाई देगी। रेल मंत्रालय ने फतेहाबाद मुख्यालय को रेल नेटवर्क से जोड़ने के सर्वे को रोक कर दिया है। यानि अभी फतेहाबादवासियों को रेल की सीटी सुनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सिरसा लोकसभा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद-अग्रहा-हिसार को रेल नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा सदन में उठाया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि हिसार और सिरसा पहले ही भारतीय रेल नेटवर्क पर भट्ट कर्ला के रास्ते पूरी तरह जुड़ा हुआ है। फतेहाबाद-अग्रहा के रास्ते हिसार से सिरसा तक सर्वे कराया गया था।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री नागर ने किया आश्वस्त

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

प्रदेश सरकार गरीब नागरिकों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजेश नागर ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार गरीबों की हितैषी है और इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है। राज्य मंत्री नागर ने बताया कि सरकार ने डिपो धारकों के कमीशन के लिए 90 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत कर दिए हैं। यह राशि जल्द ही सभी डिपो संचालकों को वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार डिपो संचालकों की समस्याओं को आगे बढ़ाएगी।

पारदर्शी राशन वितरण पर जोर

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

कैबनेट लगाए जाएंगे: डिपो के भीतर कैबनेट लाखवाने की योजना है ताकि राशन वितरण प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके। मुनाबी की व्यवस्था: राशन वितरण की सूचना गांवों और शहरों में मुनाबी के माध्यम से दी जाएगी। समस्याओं को समझती है और उनके कमीशन के मामले में कोई देरी नहीं की जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा होती है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है।



ऑक किराीक्षण: दिसंबर से राज्य मंत्री खुद राशन डिपो का औद्योगिक किराीक्षण करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवस्था कुशल रहेगी।

कानून व्यवस्था तबाह, भाजपा सरकार बेखबर: हुड्डा

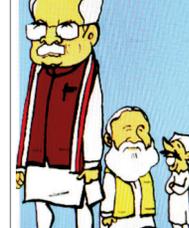
चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

हरियाणा में अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में गुरुग्राम के एक क्लब में हुए वन धमाके, कुरुक्षेत्र में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या, पुलिस और अपराधियों के बीच 35 दिनों में हुई 15 मुठभेड़ें और रोहतक में हुई गोलीबारी जैसी घटनाओं ने राज्य की विमर्श कानून व्यवस्था की तस्वीर को और भी स्पष्ट कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पहले जहां रेप, हत्या, चोरी और लूट जैसी घटनाओं का प्राण बड़ा, वहीं अब प्रदेश में बमबारी जैसी घटनाएं घटाने भी सामने आने लगी हैं। हुड्डा ने कहा कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें न तो पुलिस का डर है, न ही सरकार का। बीजेपी सरकार सत्ता के सुरू में सो रही है और अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुंह फेर चुकी है। हर सरकार की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा होती है, लेकिन इस मामले में बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

विश्वविद्यालयों में हो रहा भ्रष्टाचार: अभय चौटाला

चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिब्यून)

इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा की अधिकांश यूनिवर्सिटीज में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इनका प्रशासन कमजोर हो गया है। उनका कहना था कि सरकार ने वाइस चान्सलर ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो इस पद के योग्य नहीं हैं और इनकी मुख्य योग्यता सिर्फ आरएसएस से जुड़ी है। उन्होंने हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया।



सोल्नर पावर ल्याओ चै कोई और पावर तो दिल्ली तै मिलती र हवैवैगी।